SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Mr. Chairman, Sir, the question is about only those ex-servicemen who have been given gallantry awards, bravery awards; not about all ex-servicemen. Of course, the hon. Minister has answered and the Prime Minister has given an assurance just now. Apart from this, I would like to bring to the notice of the Government that freedom fighters have been given pension and they have also been extended railway concession, travel concession, for one year. Sir, the number of ex-servicemen who have received gallantry awards is limited. It is not in lakhs.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Two thousand.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Not in lakhs. It is a very small number. The services rendered by them are no less equal to that of the freedom fighters. The freedom fighters fought for the attainment of freedom for this country. Similarly, these people have laid down their lives to defend the Independence of this country, to safeguard the Independence of this country. The Prime Minister just now said that he will do something about it. I do not know what is that 'something'. I want a categorical statement in this House, either by the Prime Minister or the Defence Minister, that immediate steps will be taken to give this concession to the ex-servicemen and to fulfil their other demands. (*Interruptions*). The Prime Minister said 'something will be done'. I would like to know, what is that 'something'. I would like to know from the hon. Minister, what is that 'something' which they are going to give. (*Interruptions*).

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The hon. Minister should take a hard look at it.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Sir, as Mr. Reddy has pointed out, the number of ex-servicemen who have received bravery awards is not much; it is 2,485. We understand the anxiety of the hon. Members. That is why the Prime Minister also responded. Sir, in regard to the railway concession extended to the freedom fighters, it was the Prime Minister who said 'Allright; we extend it by one year'. Therefore, when the Prime Minister has said that he will look into this, I think that is enough.

Removing the upper age limit for widows/divorced women for entry into Government service

*123. DR. RATNAKAR PANDEY:†

SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to remove the upper age limit for employment in Government service for widows and divorced women; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) According to the existing orders, the upper age limit for appointment to Group 'C' and Group 'D' posts under the Central Government has been relaxed upto 35 years of age (upto 40 years for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes) in respect of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands, who have not remarried. There is no proposal to remove the upper age limit in respect of these categories.

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Ratnakar Pandey.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, मंत्री जी का जवाब मैंने पढ़ लिया है और विधवा तथा तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में मेरा प्रश्न है। विधवा के संबंध में हमारे महान कवि निराला जी ने लिखा है कि "इष्ट देव के मंदिर की दीपक सी है मलिन भारत की विधवा है।" मलिन वही होता है जो अभावग्रस्त होता है। हमारे साथी और एक अच्छे कवि "बेकल" उत्साही जी ने तलाक के संबंध में कहा है कि "दिलों को जोड़ न पाये तो फिर निफाक न दे"। निफाक का मतलब होता है दुश्मनी। दिल को जोड़े पर निफाक न दे। तल्लुकात को मजबूत करे तल क न दे... **(व्यवधान)**... मैं नाम लेकर कह रहा हूं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है "अबल जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी।" अबल वही होती है जो विधव होती है य तल कशुदा होती है। सबल नारी वह होती है जो शादीशुद होती है। मान्यवर, ... **(व्यवधान)**...
स्वामी जी, सुनिये, सदन में सांस्कृतिक और साहित्यिक माहोल भी रहना च हिये न। ... **(व्यवधान)**

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तो महिलाओं क अपमान है **(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पाण्डेय : भारत के संविधान में यह निर्देश दिया गया है कि स्त्रियों को न केवल पुरुषों के समान अधिकार दिया जाएगा बल्कि विशेष अधिकार भी प्राप्त होंगे। राज्य महिलाओं के कल्याण के लिये समान और विशेष कानून बनायेंगे। प्रायः देखा गया है कि आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों से उत्पन्न विपदाओं से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं का जीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है। मेरा पहला प्रश्न है कि समाज के इस अति संवेदनशील वर्ग की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिये उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रांतीय सरकारों को कोई दिशा निर्देश दिये हैं कि सरकारी नौकरियों में विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभी तक किस-किस प्रातीय सरकार ने इस पर अमल करने का विचार किया है राजस्थान सरकार के विषय में पांच जुलाई का जयपुर से एक समाचार है –

Rajasthan Government is taking steps to remove upper age limit for employment in Government service for widows and divorced women.

क्या निर्देश दिये गये हैं राज्य सरकारों को और क्या कार्यवाही किन-किन सरकारों ने की है ? मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ? मेरा सवाल का (ब) अंश यह है कि सरकारी कार्यालयों में आये दिन यह शिकायत मिलती रहती है कि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और उनका शोषण भी होता रहता है। उनकी शिकायतों पर विचार करने के लिये उन्हें वास्तविक संरक्षण प्रदान करने के लिये क्या सरकार कोई विशेष विभाग या सेल स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, we have not given any directions to the State Governments because personnel matters and matters relating to the State Civil Services are entirely for the State Governments to prescribe, adopt or lay down norms, but our directions and principles are always conveyed to the State Governments and we commend that the State Governments adopt the same policies and the same principles.

As far as women in the Central Government service are concerned, personnel policies are so tailored that we take note of the special difficulties of the women and we are extremely sympathetic and considerate to women employees. We have done a number of things for women. One of them is the relaxation of age limit.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Up to what age?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have read the answer. The upper age limit for Group 'C' and 'D' is 35 and in the case of Scheduled Castes and Tribes

among the women it is up to the age of 40 years. Besides, there are 26 other kinds of relaxations for various other reasons. Many of the people who apply under these categories are also women. They are the general reservations which are applicable to all. For example, the reservation for ex-servicemen, ex-NCC, also applies to women. We are sympathetic to women and we want more women to be employed.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं दूसरा सप्लीमेंटरी संक्षेप में पूछूंगा । हमारे युवा प्रधान मंत्री श्रद्धेय राजीव गांधी की सरकार का ध्यान महिलाओं के उत्थान पर जिस रूप में गतिशील है वह पहले किसी सरकार ने नहीं किया है और इसी संदर्भ में 11 फरवरी 1988 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला समिति अधिसूचित की गई थी महिलाओं संबंधी नीतियों, कानूनी मसलों तथा कार्यक्रमों और प्रशासनिक उपायों पर सलाह देने के लिये...मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह समिति किस उद्देश्य से बनायी गयी थी, कौन-कौन इसके सदस्य हैं और क्या सिफारिशें इस समिति ने की हैं ?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I think the Department of Women and Child Development is concerned with this and a question addressed to that Department will elicit a full answer.

MR. CHAIRMAN: Shri Sitaram Kesri.

SHRI DIPEN GHOSH: He must take care of the widows and divorced women.

श्री सीताराम केसरी : सभापति महोदय, विधवाओं को अनाथ कहता हूं, अबला नहीं कहता हूं। आजादी के पूर्व राजेन्द्र बाबू की अध्यक्षता में एक समिति में जब राजेन्द्र बाबू की बहिन श्रीमती भगवती देवी से एक महिला ने कहा कि हम अबला हैं तो उन्होंने राजेन्द्र बाबू से पूछा कि "अबला के का माने हाले" उन्होंने यह कहा कि जो बेसहारा है । तो वे दौड़कर माइक पर चली गयी और उन्होंने कहा कि हम महिलाएं अबला नहीं सबला हैं, पुरुषों का नेतृत्व उत्पन्न करने वाली महिलायें हैं, हम शक्ति हैं । इसलिये मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या अनाथ महिलाओं के लिये, अनाथ से मेरा मतलब है कि बेसहारा हों, अबला नहीं तो जो अनाथ महिलायें या अनाथ लड़कियां हैं उनके लिये सरकार जिला स्तर पर या ब्लाक स्तर पर या प्रदेश स्तर पर होम फार होमलेस के नाम पर – जिसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर सकती है...(**व्यवधान**) पूअर भी जो महिलायें हैं ,अनाथ है, इन अनाथ महिलाओं के लिये क्या राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रबंध करेगी जिससे कि इन अनाथ महिलाओं को लाभ हो ? अनाथ से मेरा मतलब है, अबला से नहीं जो इन्होंने कहा है । अब अन्तर पड़ गया है । आज के तलाक और पहले तलाक में अन्तर है । आज के युग में जो डाइवोर्सीज हैं वे बडी स्वावलम्बी भी होती हैं । यह बात आप जानिये । युग का परिवर्तन है, जनरेशन का अन्तर है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि नगरों में, देहातों में जो अनाथ हैं या विधवायें हैं उनके लिये क्या सरकार होम फार होमलेस के आधार पर या इनके नाम से कुछ निर्माण करेगी जिसमें तकरीबन 200 करोड़ रुपये सालाने के खर्चे का तखमीना या हिसाब किताब लगता है । क्या सरकार इस पर सोचती है ?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am answering this question in the Ministry of Personnel and I am concerned with the services and employment. But I have no doubt in my mind that all that our senior leader, Shri Sitaram Kesri, has said is very valid and I am sure his suggestions will find favour with the Government and Government will do whatever is possible.

MR. CHAIRMAN: Dr. Najma Heptulla.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Thank you, Chairman Sahib

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: On whose side are you?

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: You know which side I am on. I am on the Government side, not on the Opposition side.

Sir, the answer which the hon. Minister gave is, to some extent, heartening, but there was a very unfortunate news which I read recently in the newspapers. The Wakf Board have denied that they have any provision for giving maintenance to the divorced Muslim women. On the floor of the House, we had given some assurance to the destitute women divorcees that if nobody gives them maintenance, then the Wakf Board will give. Though I appreciate the concern that the Government is having about women and the concern of the Member who asked this question about relaxing age limit for women for employment, I also feel, as the Prime Minister is here who is very much concerned about women's development, the Government should find some measures to give meaningful employment to all the destitute women, not only in the Government service but some kind of meaningful occupation for all the destitute women whether they are Muslim women or Hindu women or any other. I direct this question humbly to the hon. Prime Minister to answer.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I entirely share the sentiments expressed by the hon. Member.

DR (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: This is not the answer. There is no assurance. Sharing the concern is no answer. It is unfortunate. Whenever I ask a question about women, either the Members laught it out or a callous answer is given. I am very sorry.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: I support her one hundred per cent.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I also entirely support the hon. Member in her criticism that whenever she asks a question about women, they laugh ata her. (*Interruptions*).

SHRI HANS RAJ BHARDWAJ: Mr. Swamy must know that she does not need his support. She can support him. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Next question. Question No. 124.

कुमारी सईदा खातन : यह महिलाओं के लिए क्वश्चन है और मैंने भी हाथ उठाया था इसलिए मुझको भी मौका दिया जाए ?

MR. CHAIRMAN: We have already spent enough time on it.

कुमारी सईदा खातून : सर मैं भी बोलना चाहती हूं ।

MR. CHAIRMAN I have called another question.

Delay in completion of the Sutlej Yamuna link Canal

*124. SHRI VIRENDRA VERMA:†
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) when was the decision to construct inter-link canal between the Nangal Hydel Channel and the Sutlej-Yamuna link first taken and what was the time schedule for the completion of the project;

(b) what are the reasons for the inordinate delay in the completion of the link canal and what steps are being taken to expedite the completion of the project; and

(c) what is the estimated cost escalation as a result of delay and by when the project is likely to be completed?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) to (c) The

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Virendra Verma.